



भारत में अंगदान

प्रलिमिंस के लिये:

[मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम-1994](#), [राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों](#), अंगदान

मेन्स के लिये:

अंगदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

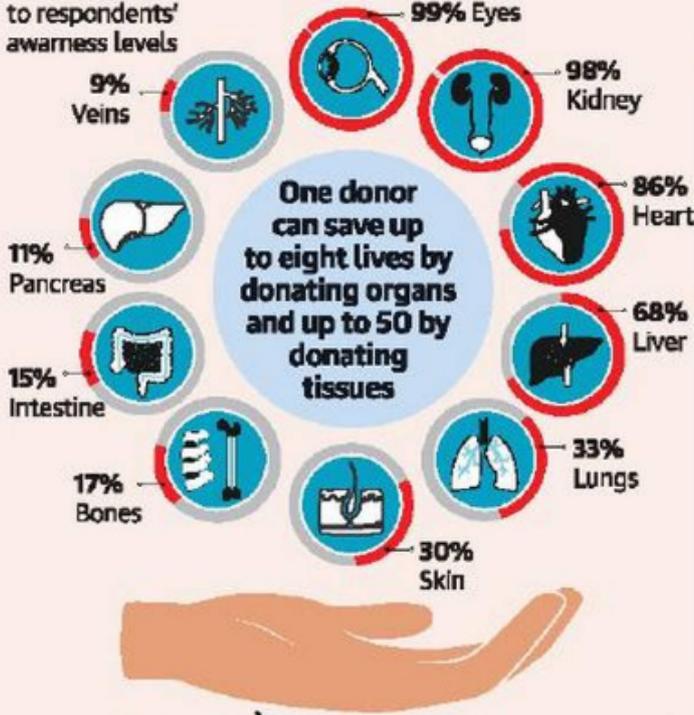
- भारत में वर्तमान में अंग दाताओं विशेष रूप से मृत दाताओं की भारी कमी के कारण गंभीर स्थिति है, जहाँ हज़ारों रोगी प्रत्यारोपण के इंतज़ार में हैं, वहीं इनमें से काफी लोगों की प्रतदिनि मृत्यु हो जाती है।
 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पहले [राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों](#) को संशोधित किया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मृत दाताओं से प्रत्यारोपण के लिये अंग प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है।
 - भारत में [मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994](#) मानव अंगों को हटाने एवं उनके भंडारण के लिये विभिन्न नियम प्रदान करता है। यह चिकित्सीय प्रयोजनों के साथ ही मानव अंगों के व्यावसायिक लेन-देन की रोकथाम के लिये मानव अंगों के प्रत्यारोपण को भी नियंत्रित करता है।

भारत में अंगदान की स्थिति:

- बढ़ती मांग के साथ नरितर कमी:
 - भारत में 300,000 से अधिक रोगी अंगदान की प्रतीक्षा सूची में हैं।
 - अंग दाताओं की संख्या अंगदान की बढ़ती मांग के अनुरूप नहीं है।
 - इस कमी के कारण अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा में प्रतदिनि लगभग 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।
- अंग दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि:
 - पछिले कुछ वर्षों में जीवति तथा मृत दोनों दाताओं की संख्या में धीमी वृद्धि देखी गई है।
 - दाताओं की संख्या वर्ष 2014 के 6,916 से बढ़कर वर्ष 2022 में लगभग 16,041 हो गई, जो मामूली वृद्धिका संकेत प्रदर्शति करती है।
 - भारत में मृतक अंगदान की दर एक दशक से लगातार प्रतदिनस लाख आबादी पर एक दाता से नीचे बनी हुई है।
- मृतक अंगदान दर:
 - इस कमी को दूर करने के लिये मृतक अंगदान दर को बढ़ाने हेतु तत्काल प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
 - स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने प्रतदिनस लाख आबादी पर 30 से 50 अंगदान दाताओं तक की उच्च अंगदान दर हासिल की है।
- जीवति दाताओं की व्यापकता:
 - भारत में सभी अंगदान दाताओं में से 85% जीवति अंगदान दाताओं का बहुमत है।
 - हालाँकि मृतकों के अंग दान, विशेषकर कडिनी, लीवर और हृदय के लिये अंगदान दाता काफी कम हैं।
- क्षेत्रीय असमानताएँ:
 - भारत के विभिन्न राज्यों में अंगदान दरों में असमानताएँ मौजूद हैं।
 - तेलंगाना, तमलिनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में मृत अंग दाताओं की संख्या सबसे अधिक है।
 - दल्लिी-NCR, तमलिनाडु, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिमि बंगाल ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ बड़ी संख्या में जीवति अंगदान दाता हैं।
- कडिनी प्रत्यारोपण:
 - भारत में कडिनी प्रत्यारोपण के मामले में मांग और आपूर्ति के बीच अत्यधिक असमानता है।
 - कडिनी प्रत्यारोपण की वार्षिक 200,000 की मांग की तुलना में प्रतविर्ष केवल 10,000 कडिनी प्रत्यारोपण किया जाता है जो कएक बड़ा अंतर है।

Which organs can be donated?

Percentage refers to respondents' awareness levels



Follow this process to pledge your organs > Visit NOTTO website and create an ID > Fill out the digital form and submit > On acceptance, you will receive an email notice > Create your donor card

अंगदान के संबंध में चुनौतियाँ:

- जागरूकता और शिक्षा का अभाव:
 - अंगदान और इसके प्रभाव के बारे में आम जनता के बीच कम जागरूकता।
 - संभावित दाताओं की पहचान करने और परिवारों को प्रभावी ढंग से परामर्श देने के लिये चिकित्सा पेशेवरों के बीच अपर्याप्त शिक्षा।
- पारिवारिक सहमति और नरिणय लेना:
 - परिवार अंगदान के लिये सहमति देने के अनिच्छुक होते हैं, भले ही मृत व्यक्ति ने अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की हो।
 - अंगदान के बारे में नरिणय लेते समय परिवारों को भावनात्मक और नैतिक दुवधियों का सामना करना पड़ता है।
- अंगों की तस्करी और कालाबाजारी:
 - अवैध अंग तस्करी और अंगों की कालाबाजारी।
 - अंगों की मांग का शोषण करने वाली आपराधिक गतिविधियाँ वैध अंगदान प्रक्रियाओं को कमजोर करती हैं।
- चिकित्सा पात्रता एवं अनुकूलता:
 - चिकित्सा अनुकूलता और अंग उपलब्धता के आधार पर उपयुक्त दाताओं और प्राप्तकर्ताओं को सुमेलित करना।
 - संगत अंगों की सीमिति उपलब्धता, जिससे रोगियों को दीर्घावधितक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
- दाता प्रोत्साहन और मुआवज़ा:
 - अंग दाताओं को वित्तीय प्रोत्साहन या मुआवज़ा देने के नैतिक नहितार्थ पर बहस।
 - नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने के साथ अंगदान दरों में वृद्धि की आवश्यकता को संतुलित करना।
- अवसंरचना और संचालन:
 - अंग पुनर्प्राप्ति, संरक्षण और प्रत्यारोपण के लिये अपर्याप्त अवसंरचना और संसाधन।
 - दाताओं से प्राप्तकर्ताओं तक वशिषकर वभिन्न क्षेत्रों में अंगों के समय पर परिवहन में चुनौतियाँ।

नए राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताएँ:

- आयु सीमा समाप्त करना:
 - जीवन प्रत्याशा में सुधार के कारण अंग प्राप्तकर्ताओं के लिये आयु सीमा समाप्त कर दी गई।
 - राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO)

के दशा-नरिदेशों ने पहले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले रोगियों को अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने से रोक दिया था।

- **अधवास की आवश्यकता न होना:**
 - अंग प्राप्तकर्त्ता पंजीकरण के लिये अधवास की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
 - 'एक राष्ट्र, एक नीति (One Nation, One Policy)' दृष्टिकोण रोगियों को किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिये पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
- **कोई पंजीकरण शुल्क न होना:**
 - अंग प्राप्तकर्त्ता के पंजीकरण के लिये पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया।
 - गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल राज्य अब रोगी पंजीकरण के लिये शुल्क नहीं लेते हैं।

नोट:

- NOTTO की स्थापना नई दिल्ली में स्थिति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services) के तहत की गई है।
- NOTTO का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग भारत में अंगों और ऊतकों के दान तथा प्रत्यारोपण हेतु खरीद, वितरण एवं रजिस्ट्री आदि गतिविधियों के लिये शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है।

आगे की राह

- अंगदान के महत्त्व को उजागर करने वाले प्रभावशाली अभियानों के लिये कलाकारों, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों के साथ साझेदारी करना।
- चिकित्सा पेशेवरों के लिये सेमिनार आयोजित करना, दाता की पहचान और परिवार परामर्श के लिये इंटरैक्टिव समुल्लेखन एवं केस स्टडीज़ का उपयोग करना।
- कार्यशालाओं और वार्ताओं के माध्यम से अंगदान के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।
- समुदाय-संचालित उन कार्यक्रमों (Community-Driven Events) की मेजबानी करना जो अंग प्राप्तकर्त्ताओं और दाताओं की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं।
- अंगदान के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने तथा इसके सकारात्मक पक्ष पर जोर देने के लिये धार्मिक नेताओं को शामिल करना।
- पट्टिकाओं और प्रमाणपत्रों के माध्यम से उनके नसिवास्वर्थ योगदान को मान्यता देते हुए अंगदान दाताओं तथा उनके परिवारों को सम्मानित करने के लिये कार्यक्रम शुरू करना।
- कुशल परिणामों के लिये अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने हेतु स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- करुणा और सहानुभूति के साथ नसिवास्वर्थ कार्य के रूप में अंगदान के विचार को बढ़ावा देना। स्रोत:

[स्रोत: द हट्टि](#)

ताप वदियुत संयंत्रों में बायोमास पेलेट्स की को-फायरिंग

प्रलिमिन्स के लिये:

[बायोमास को-फायरिंग](#), [संशोधित बायोमास नीति](#), [ताप वदियुत संयंत्र](#), [केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड](#), [प्राथमिकता क्षेत्र ऋण](#), [गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस](#), [नवीकरणीय ऊर्जा](#)

मेन्स के लिये:

बायोमास को-फायरिंग के लाभ, भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वदियुत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान संशोधित बायोमास नीति तथा 47 ताप वदियुत संयंत्रों के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिन्होंने कृषि अवशेषों से प्राप्त बायोमास पेलेट्स के साथ कोयले की को-फायरिंग को सफलतापूर्वक

एकीकृत किया है।

- वदियुत मंत्रालय (Ministry of Power) के अनुसार, मई 2023 तक 47 कोयला आधारित ताप वदियुत संयंत्रों में लगभग 1,64,976 मीट्रिक टन कृषि अवशेष-आधारित बायोमास की को-फायरिंग की गई है।

संशोधित बायोमास नीति:

- परिचय:
 - वदियुत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy- MNRE) ने **ताप वदियुत संयंत्रों (Thermal Power Plant- TPP) के संचालन में कृषि अवशेष-आधारित बायोमास पेलेट्स (Biomass Pellets) को एकीकृत करने की दिशा** में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
 - यह ऊर्जा क्षेत्र को अधिक धारणीय और पर्यावरण अनुकूल बनाने की ओर संक्रमण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- संशोधित नीति:
 - 16 जून, 2023 को वदियुत मंत्रालय ने **8 अक्टूबर, 2021** की बायोमास नीति में संशोधन किया।
 - संशोधित नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष **2024-25 से वदियुत ताप संयंत्र में 5% बायोमास को-फायरिंग** प्रक्रिया का उपयोग अनिवार्य है।
 - वित्तीय वर्ष **2025-26 से बायोमास को-फायरिंग** प्रक्रिया के उपयोग की अनिवार्यता को **बढ़ाकर 7% कर** दिया जाएगा।

बायोमास को-फायरिंग से संबंधित सरकारी हस्तक्षेप:

- वित्तीय सहायता:
 - MNRE और **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB)** ने बायोमास पेलेट्स वनिरिमाण इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिये वित्त सहायता योजनाएँ शुरू की हैं।
 - भारतीय रजिस्टर बैंक** ने **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL)** के तहत एक गतिविधि के रूप में **'बायोमास पेलेट वनिरिमाण'** को मंजूरी दी है, जिससे ऐसे पर्याप्तों के लिये वित्तीय व्यवहार्यता को प्रोत्साहन मलिया।
- खरीद और आपूर्ति शृंखला:
 - गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस** पोर्टल पर **बायोमास की खरीद के लिये** एक विशेष श्रेणी तैयार की गई है।
 - वशिवसनीय आपूर्ति शृंखला के आश्वासन हेतु वदियुत मंत्रालय द्वारा बायोमास आपूर्ति के लिये **एक संशोधित मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध (Revised Model Long-Term Contract)** पेश किया गया है।
 - राष्ट्रीय एकल खडिकी प्रणाली में उद्यम आधार को शामिल करने से बायोमास** से जुड़ी परियोजनाओं के लिये प्रशासनिक प्रक्रियाएँ सरल हुई हैं।
 - उद्यम आधार पंजीकरण प्रक्रिया स्व-घोषणा की अवधारणा पर आधारित है, जिसके तहत **MSMEs को मुफ्त में स्वयं को पंजीकृत करना तथा उद्यम आधार नंबर प्राप्त करना आसान हो गया है।**

बायोमास को-फायरिंग:

- परिचय:
 - बायोमास को-फायरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें **ऊर्जा उत्पन्न करने के लिये बायोमास-आधारित ईंधन को पारंपरिक जीवाश्म ईंधन (जैसे- कोयला, तेल अथवा प्राकृतिक गैस) के साथ एक ही वदियुत संयंत्र या औद्योगिक बॉयलर में जलाया जाता है।**
 - बायोमास पेलेट्स और कोयले की को-फायरिंग के लाभ:
 - कार्बन उत्सर्जन में कमी:** बायोमास को-फायरिंग की अवधारणा जीवाश्म ईंधन के एक हिस्से को बायोमास के साथ प्रतिस्थापित करके **ऊर्जा उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने** पर आधारित है, ऐसा माना जाता है कि यह प्रक्रिया अपने जीवनचक्र में **कार्बन-तटस्थ (Carbon-Neutral)** है।
 - कोयला आधारित वदियुत संयंत्रों में बायोमास के साथ 5-7% कोयले का प्रतिस्थापन** 38 मिलियन टन कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर सकता है।
 - नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण:** यह प्रक्रिया पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (कोयला) के साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बायोमास) को एकीकृत करने में मदद करती है, जिससे **स्वच्छ ऊर्जा मशिनरी की ओर संक्रमण** में सहायता मलित है।
 - आर्थिक और वनियामक लाभ:** को-फायरिंग से बजिली संयंत्रों को महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में बदलाव की आवश्यकता के बिना पर्यावरणीय नियमों और कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
 - बायोमास अपशिष्ट का उपयोग:** कृषि और वानिकी अपशिष्ट जो अन्यथा कषय हो जाते हैं, इन्हें को-फायरिंग के माध्यम से उत्पादक तरीकों से उपयोग में लाया जा सकता है।
- बायोमास पेलेट्स उत्पादन के लिये कृषि अवशेष: वदियुत मंत्रालय ने विभिन्न अधिष कृषि अवशेषों की पहचान की है जिनका उपयोग बायोमास पेलेट्स उत्पादन के लिये किया जा सकता है। इसमें शामिल हैं:
 - फसल अवशेष:**
 - धान, सोया, अरहर, ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूँग, सरसों, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, कॉफी आदि जैसी कृषि फसलों के अवशेष।
 - शैल अपशिष्ट:**
 - अपशिष्ट उत्पाद जैसे मूँगफली का छलिका, नारयिल का छलिका, अरंडी के बीज का छलिका आदि।

◦ अतिरिक्त बायोमास स्रोत:

- बाँस तथा इसके उप-उत्पाद, बागवानी अपशिष्ट के साथ अन्य बायोमास सामग्री जैसे- पाइन शंकु या सुई, हाथी घास, सरकंडा आदि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति पर वचिर कीजयि: (2019)

1. कार्बन मोनोऑक्साइड
2. मीथेन
3. ओजोन
4. सल्फर डाइऑक्साइड

उपरोक्त में से कौन फसल/बायोमास अवशेषों को जलाने के कारण वायुमंडल में उत्सर्जति होता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023

प्रलिमिस के लयि:

ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति, स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता, शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमकता

मेन्स के लयि:

ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति- 2023 रिपोर्ट जारी की है, जसिमें छात्रों के बीच स्मार्टफोन के उपयोग की व्यापकता पर प्रकाश डाला गया है।

- यह रिपोर्ट NGO ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (NGO Transform Rural India) और संबोधि रिसर्च एंड कम्युनिकेशंस (Sambodhi Research and Communications) के सहयोग से डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट (Development Intelligence Unit- DIU) द्वारा कयि गए सर्वेक्षण पर आधारति थी।
- इस सर्वेक्षण में 21 राज्यों के ग्रामीण समुदायों में 6-16 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के 6,229 माता-पति से प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं।

सर्वेक्षण के मुख्य नषिकर्ष:

- स्मार्टफोन का उपयोग और मनोरंजन:
 - 49.3% छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच है। 76.7% माता-पति ने बताया कि उनके बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से वीडियो गेम खेलने के लयि करते हैं, जो शैक्षिक गतिविधियों पर मनोरंजन को प्राथमकता देने का संकेत देता है।

- इसके अतिरिक्त 56.6% छात्र फ्लिपिंग डाउनलोड करने और देखने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जबकि 47.3% छात्र गाने डाउनलोड करने और सुनने हेतु स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।
- इसके विपरीत केवल 34% छात्र अध्ययन-संबंधी सामग्री डाउनलोड करने के लिये स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और केवल 18% छात्र ट्यूटोरियल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिये इसका उपयोग करते हैं।

Aspiring for higher education

The table shows parental expectations of a child's educational attainment. About 78% of parents aspire for their girls to attain graduation or higher degrees



Dropping out: Parents of a section of girls said their daughters dropped out of school to help out in the family's earnings R. RAGU

Expected level of education of child	Boy (%)	Girl (%)	Total (%)
Up to elementary	4.4	3.9	4
Up to secondary	2.4	2.8	3
Higher secondary	11.1	15.2	13
Graduation	49.6	50.3	50
Postgraduation/Ph.D.	32.5	27.8	30

■ About 80% of parents aspire for their children to become graduates or attain higher degrees

■ The survey included responses of 6,229 parents across 21 States of India.

Source: State of Elementary Education in Rural India report

■ कक्षा के आधार पर अभिदक पहुँच:

- कक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों की स्मार्टफोन तक पहुँच अलग-अलग होती है। उच्च कक्षाओं (आठवीं और उससे ऊपर) के छात्रों की स्मार्टफोन तक अधिक पहुँच (58.32%) है, जबकि 42.1% छोटे छात्रों (कक्षा I-III) तक पहुँच है।
- यह इंगित करता है कि मनोरंजन के लिये स्मार्टफोन का उपयोग सभी आयु समूहों में प्रचलित है, जो संभावित रूप से उनकी शिक्षा को प्रभावित कर रहा है।

■ माता-पिता की आकांक्षाएँ और व्यस्तता:

- 78% माता-पिता अपने बच्चों को स्नातक स्तर या उससे ऊपर की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, कति इस संदर्भ में अभिभावकों की अपने बच्चों के साथ सहभागिता काफी कम है।
- केवल 40% माता-पिता अपने बच्चों के साथ उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में दैनिकी बातचीत करते हैं, जबकि 32% सप्ताह में कुछ दिनों ऐसी बातचीत में संलग्न रहते हैं।

■ स्कूल ड्रॉपआउट का कारण:

- लड़कियों के मामले में 36.8% माता-पिता ने उल्लेख किया कि पारिवारिक कार्यों में योगदान देने के कारण उनकी बेटियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है।
 - इस बीच 31.6% ने अपने बच्चे की पढ़ाई में रुचिकी कमी को स्कूल छोड़ने के लिये ज़िम्मेदार ठहराया और 21.1% का मानना था कि इसमें घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी अहम भूमिका निभाती हैं।
- 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार, पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण वषिय-वस्तु में रुचिकी कमी थी। इसके बाद 48.7% उत्तरदाताओं को परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिये लड़कों की आवश्यकता महसूस हुई।

■ अभिभावक-शिक्षक बैठकें और सीखने का माहौल:

- 84% अभिभावकों ने नियमित उपस्थिति दर्ज की। गैर-उपस्थिति के दो मुख्य कारण हैं- अल्प सूचना और इच्छा की कमी।
- इसके अतिरिक्त 40% अभिभावकों द्वारा पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य आयु-उपयुक्त पठन सामग्री की उपलब्धता की सूचना दी गई, जो

घर पर बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिये अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

सफ़ारिशें:

- ये नषिकर्ष घर पर शैक्षिक माहौल बनाने तथा मनोरंजन और सीखने दोनों उद्देश्यों के लिये स्मार्टफोन के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लक्ष्य प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

स्रोत: द हद्रि

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023

प्रलिस के लिये:

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023, अंडमान और निकोबार कमांड, भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना कमांड।

मेन्स के लिये:

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023 की मुख्य वशिषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने सशस्त्र बलों के बीच दक्षता, अनुशासन और एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से [अंतर-सेवा संगठन \(कमान, नियंत्रण और अनुशासन\) वधियक, 2023](#) पारित किया है।

अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023:

- पृष्ठभूमि:
 - वर्तमान में [सशस्त्र बल](#) के कर्मियों को उनके वशिषिट सेवा अधिनियमों- [सेना अधिनियम, 1950](#), नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 में नहिति प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।
 - हालाँकि इनके कार्यों की वधि प्रकृति ने कभी-कभी अंतर-सेवा प्रतषिठानों में प्रभावी [अनुशासन, समन्वय और त्वरति कार्यवाही](#) हेतु चुनौतियाँ पैदा की हैं।
 - अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) वधियक, 2023 अपने दूरदर्शी प्रावधानों के साथ इन चिंताओं का समाधान करता है।
 - वर्तमान सेवा अधिनियम के नियम एवं वनियम, जो कई वर्षों तक समय और कानूनी जाँच का सामना कर चुके हैं, [ISO वधियक, 2023](#) के तहत किसी भी बदलाव के अधीन नहीं हैं।
- प्रमुख वशिषताएँ:
 - प्रयोज्यता: यह वधियक सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी नियमति कर्मियों पर लागू है।
 - इसके अतिरिक्त [केंद्र सरकार भारत में स्थापति और संचालति](#) किसी भी बल को नामति करने का अधिकार रखती है, जसि पर वधियक के प्रावधान लागू होंगे।
 - अंतर-सेवा संगठन: मौजूदा अंतर-सेवा संगठनों को वधियक के तहत गठति माना जाएगा। इनमें [अंडमान और निकोबार कमांड, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी](#) शामिल हैं।
 - केंद्र सरकार एक अंतर-सेवा संगठन का गठन कर सकती है जसिमें सेना, नौसेना और वायु सेना- तीनों सेवाओं में से कम-से-कम दो से संबंधति कर्मी हों।

नोट:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त कमान भारतीय सशस्त्र बलों की पहली त्रि-सेवा थरिटर कमान/कमांड है, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थति है।
 - भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में 17 कमांड हैं। थल सेना और वायु सेना की 7-7 कमानें हैं। नौसेना के पास 3 कमान हैं।
 - प्रत्येक कमांड का नेतृत्व 4-स्टार रैंक के सैन्य अधिकारी द्वारा किया जाता है।

- **वसितारति कमान और नयित्रण प्राधकिरण:** वधियक के केँद्रीय सदिधांतों में से एक अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ (Commander-in-Chief) या ऑफिसर-इन-कमांड (Officer-in-Command) को कमान और नयित्रण प्राधकिरण का वसितार करना है।
 - मौजूदा ढाँचे के वपिरीत जहाँ इन अधकिारियों के पास अन्य सेवाओं के कर्मियों पर अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक शक्तियों का अभाव है, वधियक उन्हें पूर्ण कमान और नयित्रण का अधकिार देता है।
 - इसमें अनुशासन बनाए रखना तथा सेवा कर्मियों द्वारा कर्तव्यों का उचित नषिपादन सुनशिचति करना शामिल है।
- **कमांडिंग ऑफिसर (Commanding Officer):** यह बलि एक कमांडिंग ऑफिसर की अवधारणा पेश करता है, जो किसी यूनिट, जहाज़ या प्रतषिठान की देख-रेख के लयि ज़मिमेदार होता है।
 - यह अधकिारी अपने यूनिट-वशिषिट कर्तव्यों के अलावा अंतर-सेवा संगठन के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड द्वारा सौंपे गए कार्यों को भी करता है।
- **केँदर सरकार का प्राधकिार:** एक अंतर-सेवा संगठन का अधीक्षण केँदर सरकार में नहिती होगा।
 - सरकार ऐसे संगठनों को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामान्य प्रशासन या सार्वजनिक हति के आधार पर भी नरिदेश जारी कर सकती है।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/09-08-2023/print>

